जलवायु परिवर्तन पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक में प्रधानमंत्री का वक्तव्य
(दिनांक 9 जुलाई, 2008)

मैं इस तथ्य का स्वागत करता हूं कि हम सब दीर्घकालिक सहयोगात्मक कार्रवाई के जरिए यूएनएफसीसीसी के कार्यान्वयन के लिए गंभीर विचार-विमर्श में संलग्न हैं ।

यह बहुत आवश्यक है कि कनवेन्शन के प्रावधानों व सिद्धांतों, खासतौर से सामान्य परन्तु विभिन्न उत्तरदायित्वों और अपनी-अपनी क्षमताओं के मद्देनजर, को इन विमर्शों में पूरा सम्मान दिया गया है । उनके नतीजों को कथनी और करनी में लागू करना है ।

गरीबी उपशमन सभी विकासशील देशों की पहली और अहम प्राथमिकता है ।

भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी आधुनिक ऊर्जा संसाधनों से विहीन हैं । हमारी एक चौथाई आबादी रोजाना एक डॉलर से भी कम आय पर जिंदगी बसर करती है क्ष

जब हम खुद पर जलवायु परिवर्तन का असंगत प्रभाव पर विचार करते हैं तब त्वरित विकास की आवश्यकता बढ ज़ाती है । विकासशील देशों के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं और उन्हें अपने संसाधनों को खाद्य सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और दुर्लभ जल संसाधनों के प्रबंधन में लगाना पड़ता है ।

और ये हालात उस समय हुए हैं जब हमारे बढते हुए ऊर्जा खर्च ने हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है ।

इसीलिए दीर्घकालीन और त्वरित आर्थिक विकास विकासशील देशों के लिए बहुत आवश्यक है, और इस समय हम अपने उत्सर्जन पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों के बारे में सोच भी नहीं सकते ।

इसके अलावा सार्वजनिक व निजी विकास हस्तांतरण और प्रवाह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए । इसके अलावा विकासशील देशों को नए व अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए ।

स्वीकृत ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन में विकसित देशों की कटौती करने की दिशा में कोई प्रगति हमें अब तक नजर नहीं आई है । यकीनन पूर्वानुमान यही है कि उनका उत्सर्जन आने वाले वर्षों में बढ़ेगा ।

इसे बदलना होगा और आपको (जी-8) वही नेतृत्व करना होगा, जिसका वायदा आपने किया था कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सकारात्मक तौर पर कम किया जाएगा ।

मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत एक जिम्मेदार देश है और अपने अंतर्राष्ट्रीय तकाजों को खूब समझता है । भारत वहनीय विकास पथ पर बढने के लिए प्रतिबद्ध है। यद्यपि भारत में प्रति व्यक्ति स्तर पर उत्सर्जन विश्व में सबसे कम है और हम ज्यादा उत्सर्जन करने वालों में शामिल नहीं है, इसके बावजूद हमने हाल में ही जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना स्वीकार की है ।

यदि हमें विश्व का समर्थन मिले खासतौर से वित्तीय प्रवाह व प्रौद्योगिकी के संदर्भ में तो हमारी कोशिशों में यकीनन इजाफा होगा ।

भारत इस बात पर दृढ है कि आर्थिक विकास व प्रगति के मार्ग पर बढते हुए भी हमारा प्रति व्यक्ति उपर्युक्त विकसित देशों के उत्सर्जन से आगे नहीं जाएगा ।

लेकिन यह अवधारणा विकसित देशों के लिए चुनौती भी है । आप जितनी जल्दी अपने उत्सर्जन में कटौती करेंगे, उतना ज्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा ।

मैं चांसलर मार्केल, राष्ट्रपति सारकोजी और प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने उपर्युक्त बिंदु का स्वागत किया है ।

यदि हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ईमानदारी से हल करना चाहते हैं तो जरूरी यह है कि हम वहनीय विकास व ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के समान अधिकार को मान्यता प्रदान करें ।

कनवेन्शन के मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न्यायसंगत और कार्बन स्पेस प्रतिमान भी महत्वपूर्ण हैं ।

और सच्ची कामयाबी के लिए, हमें दुनिया भर में अवहनीय उपभोग के तरीकों और जीने के ढंग को बदलना होगा ।

मैं यह भी मानता हूं कि उपशमन और अनुकूलन के लिए प्रौद्योगिकी रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण कारक है ।

विकासशील देशों में सस्ती उन्नत व स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, उनके हस्तांतरण, उपयोग और फैलाव के लिए विकासशील और विकसित देशों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान व विकास में तेजी लाई जानी चाहिए ।

उन्नत साफ प्रौद्योगिकियों के लिए उचित आईपीआर कानूनों की जरूरत है ताकि अभिनव प्रयोग करने वालों को मिलने वाला प्रतिफल पर्याप्त लाभकारी हो । इसके साथ ही इन्हें विकासशील देशों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाए । बेशक, इस बात में दम है कि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को वैश्विक सार्वजनिक संपदा माना जाए ।

यह भी जरूरी है कि मानक व नियम विकासात्मक संदर्भों के अनुरूप हों ।

जलवायु परिवर्तन यकीनन हम सबके लिए बड़ी चुनौती है ।

लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना इस्तेमाल पहले से जटिल चुनौतियों में शर्तें जोड़ने के लिए किया जाए जिनका सामना हम विकासशील देश कर रहे हैं । इनका इस्तेमाल

आर्थिक यथास्थिति कायम रखने और अन्य उपायों से संरक्षतावाद थोपने के प्रयासों के तौर पर नहीं होना चाहिए ।

इसे हमें चुनौती और अवसर की तरह लेना चाहिए । हमें मानवता के भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोगात्मक रूप और मिलजुलकर काम करना चाहिए ।

धन्यवाद ।

***